क्षेत्र/स्टेशन

नागालैण्ड	**तमिलनाडु**
48. दीमापुर	55. तंजावूर
दक्षिणी क्षेत्र	56. नैवेली
आंध्र प्रदेश	57. तिरूचिरापल्ली
49. कुडप्पाह	58. मदुरै
50. रामागुंडम	
51. विशाखापत्तनम	**केरल**
कर्नाटक	59. कालीकट
52. बेलैरी	60. तिवेन्द्रम
53. मैसूर	**केन्द्रशासित दमन एवं द्वीव**
54. हुबली	61. दमन

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

249. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लम्बाई कितनी है ;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय किये गये धन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उन लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया है ; और

(घ) आठवीं योजना में उत्तर प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों और मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण कार्य के लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 11 है। इनकी लम्बाई इस प्रकार है :—

क्रम सं.	रा. रा. स.	लम्बाई (कि.मी.)
1.	2	777
2.	3	26
3.	7	128
4.	11	51
5.	24	431
6.	25	237
7.	26	128
8.	27	43
9.	28	311
10.	29	196
11.	56	285
	योग	2613

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

व्यय (लाख रु.)

वर्ष	(क) विकास	(ख) रख-रखाव और मरम्मत
1986-87	2741.86	1111.41
1987-88	3115.79	945.11
1988-89	3869.79	1456.63
1989-90	5560.12	1265.66
1990-91	6516.36	1142.89

(ग) पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की मंजूरी के लक्ष्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं रहा, जैसा कि नीचे दर्शाए गए आंकड़ों से स्पष्ट है :—

	छठी योजना		सातवीं योजना	
	योजनागत प्रावधान (करोड़ रु०)	मंजूरी	योजनागत प्रावधान (करोड़ रु.)	मंजूरी
गुजरात	34.52	39.08	203.40	250.58
उत्तर प्रदेश	67.23	52.86	303.90	263.70

(घ) चूंकि आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित राशि के बारे में बताना अभी समय पूर्व होगा। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव गैर-योजनागत निधियों में से किया जाता है और संसाधनों की समग्र उपलब्धता के आधार पर वर्ष दर वर्ष धनराशि आबंटित की जाती है ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक आवासों, होटलों और यात्री-निवासों का निर्माण

250 **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश में जिला-वार बनाए गए पर्यटक आवासों, होटलों, और यात्री-निवासों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) ये होटल आदि किन-किन स्थानों पर हैं और इसके लिए उन्हें कितनी धनराशि की आर्थिक सहायता दी गई है ;

(ग) इस समय केंद्रीय सरकार के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्ताव हैं; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (**श्री माधवराव सिंधिया**) : (क) और (ख) केंद्रीय पर्यटन विभाग ने गत पांच वर्षों के दौरान पर्यटक होटलों या होस्टलों का निर्माण कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता नहीं दी है । तथापि, इलाहाबाद में एक यात्री निवास तथा माल्दीपुर में एक अन्य यात्री निवास के लिए वित्तीय सहायता (स्वीकृत राशि क्रमशः 29.42 लाख और 40.20 लाख रुपए) दी गई है ।

(ग) और (घ) 1991-92 के दौरान , अयोध्या और चित्रकूट में दो यात्री निवासों के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है । उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अनुमानों सहित विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं ।

उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में नई सूती मिलें

251. श्री ईश दत्त यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सहकारी क्षेत्र में राज्यवार कितनी सूती मिलें हैं ;

(ख) क्या ये मिलें हथकरघा और विद्युत-चालित करघा उद्योगों को मांगों को पूरा करने में सक्षम हैं ;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, कानपुर एवं सुल्तानपुर जिलों में नई मिलों की स्थापना करने का कोई विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार की कितनी मिलें स्थापित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार मिलों की संख्या 120 है । (**नीचे देखिए**) ।

(ख) सहकारिता क्षेत्र की मिलों के अलावा हथकरघा तथा विद्युत करघा उद्योग की मांग अन्य क्षेत्रों तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों आदि द्वारा भी पूरी की जाती है ।

(ग) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, और सुल्तानपुर में नई मिल स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

30 सितम्बर, 91 की स्थिति के अनुसार, सहकारिता क्षेत्र में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों तथा फ्रिक बुनाई एककों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :—

राज्य	सहकारिता मिलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	9
असम	1